बात जहर है कि हमारी फिगर्स के मुताबिक ग्रन-इम्पलायड पर्सन्स का बैकलाग 20.6 मिलियन है 1980–85 के बीच में उस में 29.5 मिलियन का एडीशन हो जाएगा जिस में जो जाब देने का हम प्रावधान सोच रहे हैं सरकारी और दूसरी एजेन्सीज के माध्यम से वह 49.2 मिलियन पर्सन्स हैं। उस में जो बेकार रह जाएंगे वह हमारी सूचना के मुताबिक अभी तक 0.9 मिलियन लोग हैं।

DR. KARAN SINGH : Mr. Speaker, Sir, the educated unemployed represents one of the most tragic waste of human and psychological resources of this country. Some schemes have been made but, evidently, they are not having an impact on the problem.

Will the hon. Minister be pleased to tell the House whether the Government is considering some way of mobilising and utilising the energies of these unemployed youth by setting up something on the lines of a National Service corps with these young people at a small cost, who can be given the socially useful tasks of performing tree plantation, social services, sanitation and so on, so that they do not become a burden on the society but are able to contribute something to developing of a New India ?

SHRI BALESHWAR RAM : My reply to this is this. I have noted down his suggestion.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, in view of the fact that the Central Government has failed miserably to provide employment for all, will the Government feel it a duty to provide at least some relief to the educated youth in the shape of unemployment relief as is being done in West Bengal and Maharashtra ? Will the Central Government be ready to do that ?

SHRI BALESHWAR RAM : This is a State subject. The States are doing that.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Mr. Speaker, Sir, this is not at all a state subject. Will he come forward with a scheme ?

SHRI BALESHWAR RAM : I have noted down your suggestion.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Well, at least you have noted down my suggestion.

मूंगफली का उत्पादन

312. **श्री नरसिंह मकवाणा** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में इस वर्ष कितने हैक्टार भूमि में मूंगफली का उत्पादन किया गया है और इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

(ख) इस वर्ष मूंगफली के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ;

(ग) मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) इस वर्ष देश में अन्य तिलहनों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION, IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Area sown to groundnut from the 1st July, 1980 to the 30th June, 1981

was 66.8 lakh hectares. A state-wise break up is laid on the Table of the House. It is too early to estimate the area sown to groundnut from 1st July, 1981 to the 30th June, 1982.

(b) and (d). It is too early to give any estimate in this regard.

(c) The following steps are being taken to increase the production of oilseeds including groundnut in the country :—

1. Under the Centrally Sponsored Scheme for the Development of oilseeds, an intensive programme is under implementation in 10 States in 1981-82. The scheme aims at demonstrations on farmers' fields, strengthening of seed production and distribution arrangements, expansion of plant protection measures and training for farmers and extension workers.

2. Extension of irrigated are a under oilseed crops.

3. Increase in areas under non-traditional oilseed crops namely soyabeen and sunflower.

4. Launching up of special projects on production of groundnut in Saurashtra region of Gujarat and soyabeen in Madhya Pradesh.

5. Increasing the area under short duration varieties of oilseeds through catch-cropping and inter-cropping.

6. Fixation of minimum support prices to ensure that the farmer receives remunerative prices for his produce.

Statement

Estimate of area sown to groundnut in major States, 1980-81

(*Lakh hectares*)

State	Area
Andhra Pradesh	12.8
Gujarat	20.0
Karnataka	7.7
Madhya Pradesh	3.3
Maharashtra	7.3
Orissa	1.8
Punjab	0.9
Rajasthan	2.1
Tamil Nadu	8.7
Uttar Pradesh	1.2
All India	66.8

श्री नरसिंह मकवाणा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि गुजरात में प्रति हैक्टेयर कितना उत्पादन होता है और दूसरे राज्यों में क्या होता है?

राव वीरेन्द्र सिंह : उत्पादन इरिगेटेड एरिया का अलग है और नान-इरिगेटेड एरिया का अलग है। अगर माननीय सदस्य एवरेज जानना चाहते हैं तो गुजरात के लिए नेशनल एवरेज तो मैं बता सकता हूं, इस वक्त अलग अलग फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह बता दीजिए, फिर भेज दीजिए।

श्री नरसिंह मकवाणा : मंत्री महोदय ने एक जवाब तो दिया नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े भेज देंगे।

श्री नरसिंह मकवाणा : गुजरात में मूंगफली और मध्य प्रदेश में सोयाबीन

के लिए सरकार कौनसी योजना शुरू करना चाहती है और कब से शुरू करेगी? उसका कोई परिणाम निकला है या नहीं?

राव बीरेन्द्र सिंह: गुजरात के लिए 35 करोड़ का स्पेशल प्रोजेक्ट पिछले साल हमने मंजूर किया था जिस से अब जो 68 एकड़ इरिगेटेड ग्राउन्डनट को कल्टीवेशन होती है, उसको 2 लाख हैक्टेयर तक बढ़ाएंगे। इस तरीके से अगले 4 साल में 1981 से 84 तक गुजरात को पैदावार कुल जो अब 18 लाख टन के करीब है, यह 27 लाख टन तक ले जाने का अन्दाजा है। यह प्रोजेक्ट काफी मुफीद है और लोगों ने इसे बहुत पसन्द किया है। दूसरी स्टेट्स से भी इसके लिए मांगें आ रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जनवरी में दूसरी स्टेट्स को भी एक चिट्ठी लिखी थी। उन सब ने सोयाबीन और ग्रायलसीडज की उस प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की है, जो गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया ने गुजरात को दी है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: मैं जानना चाहता हूं कि देश में खाने के तेल की कमी को देखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि बिहार में, और खासकर उत्तरी बिहार में, ऐसी जमीन है, जहां मूंगफली उगाई जा सकती है, क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत उत्तरी बिहार में ज्यादा से ज्यादा मूंगफली पैदा की जा सके, ताकि खाने के तेल की कमी की पूर्ति की जा सके।

राव बीरेन्द्र सिंह: इन सारी बातों पर विचार हो रहा है।

श्री रामलाल राही: मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो स्टेटमेंट दिया है, उस में प्रदेशवार बताया गया है कि किस प्रदेश में कितने क्षेत्रफल में मूंगफली बोई गई है। उसके देखने से मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में सब से कम एरिया में मूंगफली बोई गई है। आपको याद होगा कि मैंने इस सवाल को बहुत पहले उठाया था कि उत्तर भारत में निरन्तर कई बरसों से मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आ रही है। वहां क्वान्टिटी भी खराब है और क्वालिटी भी खराब है। इस लिए किसान मूंगफली की बुवाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि हमारे देश में तेल का उत्पादन घट रहा है और तेल के मामले में हम निरन्तर दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उत्तर भारत में, और खासकर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई में—यह मूंगफली का क्षेत्र है और सीतापुर उत्तर भारत की सब से बड़ी मंडी है—उत्पादन क्यों कम हुआ है, और वह कम हुआ है, यह आंकड़ों से प्रदर्शित होता है, क्योंकि बुवाई बहुत कम हुई है। क्या मंत्री महोदय कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि मूंगफली की क्वान्टिटी और क्वालिटी में सुधार हो और लोग मूंगफली बोने के लिए ज्यादा उत्साहित हों, ताकि हम तेल के मामले में आत्म-निर्भर हो सकें?

राव बीरेन्द्र सिंह: इस में शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में मूंगफली की कल्टीवेशन के लिए एरिया काफी बढ़ा नहीं है। पिछले कई सालों से इसका कल्टीवेशन साढ़े सात और 8 लाख हैक्टेयर के बीच में रहा है। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज पैदा किए जा रहे हैं, जिस से और ज्यादा लोग मूंगफली बोना शुरू कर दें और उनको ज्यादा फायदा हो। उत्तर प्रदेश में

दूसरे प्रान्तों की निस्बत यील्ड बहुत कम है, लेकिन पिछले साल की निस्बत बढ़ी है। 1980-81 में उत्तर प्रदेश में 84 किलोग्राम पर हेक्टेयर यील्ड थी। इसके मुकाबले में गुजरात में, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने सवाल किया है, एवेरेज यील्ड 283 किलोग्राम पर-हेक्टेयर थी। लेकिन इस में बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि बहुत से प्रान्तों में इस से दुगनी यील्ड होती है। उड़ीसा में यील्ड काफी ज्यादा है—583 के जी है, जबकि तामिल नाडु में 302 है, वैस्ट बंगाल में मूंगफली की काफी.....। मैं मूंगफली की फिगर्ज नहीं दे रहा था, मैं सेसामम (तिल) की फिगर्ज पढ़ रहा हूं। यू०पी० की फिगर्ज इस वक्त मेरे पास नहीं है। पहले मैंने ग्राउंडनट की नेशनल एवेरेज यील्ड की गलत फिगर बताई है। इस वक्त हमारी नेशनल ऐवेरेज यील्ड 711 किलोग्राम के करीब है, जिसके मुकाबले में यू० पी० की यील्ड बहुत कम है।

News Item "Orissa Project may lose World Bank Aid"

*313. SHRI HARINATHA MISRA : Will the minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report as appeared in the Indian Express dated 12 August, 1981, under the caption, "Orissa Project may lose World Bank aid" ;

(b) if so, the charge levelled and the reaction of the Union Government thereto ;

(c) whether the authorities had actually split up the project into two portions "against the lender's clear directive to treat it as a single tender"; if so, the reasons behind the violation of the directive ; and

(d) the latest position with regard to the attitude of the World Bank and fate of the Project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The implementation of the project rests with the State Government and the final decision regarding the award of contracts has to be taken by the Government of Orissa in consultation with the International Development Association, an affiliate of World Bank. The Government of India is not involved in the process of awarding of contracts. It is learnt that no final decision has yet been taken by Government of Orissa in this regard.

(d) The Government of India has not received any communication from the international Development Association in this regard.

SHRI HARINATHA MISRA : Is it a fact that Orissa Government entered into an agreement with the World Bank with the knowledge, support and blessing of the Government of India ?

SHRI Z. R. ANSARI : It is a fact that this agreement between the Orissa Government and the IDA, an Associate of the World Bank, was entered into with the blessing of the Government of India.

SHRI HARINATH MISRA : Is it a fact that the local Government had been trying to favour a company, formed as late as February 1981, which has got no experience, no financial viability, and no know-how against the guidelines of the World Bank and so, the entire project is at a standstill because of this stalemate between the Orissa Government and the World Bank. In the circumstances will the Union Government make it a point to intervene in the interest of the